

बिज़नेस स्टैंडर्ड

वर्ष 12 अंक 145

दरों में कटौती से इतर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के बारे में माना जा रहा है कि वह इस सप्ताह एक बार फिर ब्याज दरों में कटौती करेगी। हालांकि खुदरा मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति जून में बढ़ी लेकिन निकट भविष्य में उसके 4 फीसदी का स्तर पार करने की आशंका नहीं है। बहरहाल, फिलहाल बढ़ा सवाल यह है कि क्या एक

और बार दरों में कटौती आर्थिक गतिविधि बहाल करने में सहायक होगी ?

भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर मंदी में है और वाहनों की बिक्री, कंपनियों के नतीजे तथा आधारभूत क्षेत्रों के ताजा आंकड़ों जैसे संकेतक यह बता रहे हैं कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वृद्धि दर, जनवरी-मार्च तिमाही में दर्ज 5.8 फीसदी से भी कम रहेगी। इतना ही

नहीं वृद्धि को सहायता पहुंचाने के लिए किसी भी तरह की राजकोषीय गुंजाइश भी नहीं है। हकीकत यह है कि कर संग्रह के आंकड़े बताते हैं कि बजट के लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा और इसके लिए व्यय में कटौती करनी पड़ सकती है। उच्च व्यय के समायोजन की सलाह भी नहीं दी जा सकती है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र का ऋण पहले ही काफी बढ़ा हुआ है।

भारतीय अर्थव्यवस्था को शेष विश्व से भी सहायता मिलने की उम्मीद नहीं है। वैश्विक अर्थव्यवस्था गति खो रही है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने गत सप्ताह ब्याज दरों में कटौती कर दी। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद यह पहला अवसर है जब कटौती की गई है। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे कारोबारी

युद्ध, ब्रेक्सिट से जुड़ी अनिश्चितता और पश्चिम एशिया का भूराजनीतिक तनाव भी वैश्विक वृद्धि के लिए खतरा हैं।

दिए गए आर्थिक परिदृश्य में यह सवाल पृष्ठना उचित है कि वृद्धि को गति देने के क्रम में मौद्रिक नीति के लिए क्या कुछ उचित होगा। जून में हुई बैठक में आरबीआई के गवर्नर शक्तिदास ने कहा, 'वृद्धि और मुद्रास्फीति के नए समीकरण के बीच मौद्रिक नीति के मोर्चे पर निर्णायक कदमों की आवश्यकता है।' वृद्धि के पूर्वानुमान तब से अब तक खराब ही हुए हैं। ऐसे में इस सप्ताह ब्याज दरों में कटौती से इतर तमाम अंशधारकों की नजर इस बात पर होगी कि केंद्रीय बैंक वृद्धि को किस हद तक समर्थन देने को तैयार है। चूंकि आरबीआई का प्राथमिक लक्ष्य मुद्रास्फीति को

4 फीसदी के आसपास रखना है इसलिए यह देखना अहम होगा मौद्रिक नीति समिति आने वाली तिमाहियों में मुद्रास्फीति और वृद्धि में कैसी प्रगति देखती है ? अगर वह वृद्धि में उल्लेखनीय धीमापन आने की उम्मीद करती है तो मौद्रिक मोर्चे पर उदारता देखने को मिल सकती है। कीमतों में ज्यादा इजाफा होने की उम्मीद नहीं है क्योंकि आर्थिक गतिविधियां पहले ही धीमी हो रही हैं। हालिया महीनों में मूल मुद्रास्फीति में गिरावट से यह परिलक्षित भी हुआ है।

इसके अलावा एमपीसी अगर यह बता दे कि वह वास्तविक ब्याज दर को किस स्तर पर रखना चाहती है और किन हालात में उसमें कमी की जाएगी तो और भी अच्छा होगा। इससे व्यवस्था में यह भरोसा पैदा होगा कि

केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति तय करने के अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होगा। यह भी अहम है कि वित्तीय बचत को हतोत्साहित न किया जाए। अर्थव्यवस्था को नीतिगत कदमों का लाभ मिलने के लिए यह आवश्यक है कि केंद्रीय बैंक दरों के पारेषण पर काम करे।

मौद्रिक समायोजन केवल एक सीमा तक ही कारगर हो सकता है और यह सार्थक सुधार के लिए पर्याप्त न होगा। सरकार को भूमिका निभानी होगी। कुछ हालिया कदम मसलन अमीरों के लिए आयकर की उच्च दर, उच्च आयत शुल्क, अफसरशाही की अतिरिक्त शक्ति आदि ने कारोबारी भरोसे पर असर डाला है। कुछ हालिया निर्णयों तथा अर्थव्यवस्था के संचालन का दोबारा आकलन सरकार के लिए इस दिशा में शुरुआती कदम हो सकता है।



अजय मोहंती

तीन दलबदल, छह हत्याएं तीन बलात्कार, एक दल

कुलदीप सिंह सेंगर, संजय सिंह और साक्षी महाराज के किस्से हमें हमारी राजनीति, पुलिस और कानून व्यवस्था तथा भारतीय जनता पार्टी के बारे में काफी कुछ बताते हैं।

लगातार दलबदल करने वाले कम से कम ढाई राजनीतिक व्यक्ति बीते दिनों सुर्खियों में रहे। इनमें पहला और सबसे सुना हुआ नाम है कुलदीप सिंह सेंगर का जो उन्नाव बलात्कार-हत्याकांड में कुख्यात हुए। दूसरा नाम है अमेठी के भूतपूर्व 'राजा', पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री संजय सिंह का जो हाल ही में कांग्रेस की डूबती नौका से कूदे हैं। तीसरा नाम है साक्षी महाराज, जो उन्नाव से भाजपा के सांसद हैं। हमने उन्हें आधा गिना है क्योंकि हाल में उनका कोई राजनीतिक या आपराधिक कृत्य सुर्खियों में नहीं आया है। उन्होंने जिन्न करने लायक काम यही किया है कि वह जेल में सेंगर से मिलने गए। यह मुलाकात लोकसभा चुनाव में सहायता के बंदले धन्यवाद सापन था। ये तीनों बार-बार दल बदलते रहे हैं। इनका नाम हत्याओं के छह मामलों से जोड़ा जाता रहा है, हत्याओं के कई मामले अनसुलझे भी हैं। इसी तरह बलात्कार के कम से कम तीन अनसुलझे मामलों से इनका नाम जुड़ा है।

तीनों की मांग निरंतर बनी रहती है। उन्हें अपनी जाति और क्षेत्र के वोट मिलते हैं। उन्हें कानून से निपटना आता है और इनके पास ऐसी खूबी है जिसके कारण तमाम राजनीतिक दल इन्हें क्षमता, ईमानदारी और नैतिकता से परे मानते हैं, वह है चुनाव जीतने की क्षमता। संयोगवश ये तीनों भाजपा में हैं। कम से कम कुछ रोज पहले तक तो ऐसा ही था जब तक कि सेंगर को निकाल नहीं दिया गया। एक कथित अपराधी, या डॉन या कहे बाहुबली के आपराधिक जीवन पर ही इनका केंद्रित हो जाते हैं कि हम उसे रंगीन सार्वजनिक जीवन की अनदेखी कर बैठते हैं। सन 2002 में स्थानीय 'ददू' बसपा के टिकट पर उन्नाव से चुनाव जीतकर पहली बार माननीय विधायक बन गए।

इसके बाद वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और 2007 और 2012 के चुनाव पास की बांगेरमऊ और भगवंत नगर

सीटों से जीते। यही वह वक्त था जब यह माना जाने लगा था कि समाजवादी पार्टी आपराधिक माफियाओं को संरक्षण दे रही है, खासकर यादवों और राजपूतों को। सन 2017 में हवा का रुख भांपते हुए वह भाजपा में चले गए और पुनः विधायक बने। उनके भाजपा विधायक बनने के तीन महीने बाद ही वह किशोरी उनके पास नौकरी में सहायता मांगने आईं और उसने शिकायत की कि इसके बजाय विधायक ने उसके साथ 'बलात्कार' किया और 'मेरे आंसू पोंछते हुए कहा कि वह मुझे रोजगार दिलाने में मदद करेंगे।'

संजय सिंह इतनी बार दल बदल कर चुके हैं कि मैं आशंका में आपको सूची नहीं दे पा रहा कि कहीं गलती न कर बैठूं। वह हत्या के एक चर्चित मामले से जुड़े रहे, हालांकि बाद में बाइज्जत बरी हो गए।

यह मामला 1988 का है जब लखनऊ में बैडमिंटन के राष्ट्रीय चैंपियन सैयद मोदी की सुपारी देकर हत्या करा दी गई थी। संजय सिंह इस हत्या के प्रमुख संदिग्ध थे लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस और सीबीआई उनके खिलाफ कुछ नहीं तलाश पाई और वह सबूतों के अभाव में छूट गए। व्यक्ति जब तक दोषी न सिद्ध हो वह निर्दोष होता है, हम सभी को यह मानना चाहिए। यह भी हत्या का वैसा ही मामला सिद्ध हुआ जहां भाड़े के हत्यारों को दंड मिला लेकिन प्रमुख अभियुक्त तक कोई नहीं पहुंचा। भाड़े के दो हत्यारों में से एक भागवती सिंह को सजा हुई और दूसरे अमर बहादुर की सुनवाई के दौरान हत्या हो गई। हत्या के बाद संजय सिंह ने सैयद मोदी की विधवा अमिता मोदी (पूर्व में कुलकर्णी) से विवाह कर लिया। जिस समय सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी लगभग उसी समय विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस से

बगावत कर प्रधानमंत्री बन चुके थे। वह सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह के रिश्ते में आते थे। संजय सिंह भी कांग्रेस छोड़कर उनके साथ हो लिए। एक दशक बाद वह भाजपा में शामिल हो गए और सन 1998 में कैप्टन सतीश शर्मा को हराकर अमेठी लोकसभा चुनाव जीत गए। लेकिन संसद में उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा क्योंकि वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई।

सन 1999 के चुनाव में वह अपने पुराने मित्र और मार्गदर्शक राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी के खिलाफ भाजपा के टिकट पर अमेठी से चुनाव मैदान में उभरे। सोनिया ने सुरक्षित रहने की दृष्टि से बेल्लारी से भी चुनाव लड़ा था। उस वक्त मैंने अमेठी में समय बिताया था और सिंह के अभियान को कवर किया था। उनका एक नारा आज भी मेरे कानों में गूंजता है: संजय सिंह के डर की मारी, सोनिया भाग गई बेल्लारी। सोनिया अमेठी और बेल्लारी दोनों जगह से जीतने में कामयाब रहें।

हवा बदली और 2003 में वह दोबारा कांग्रेस में लौट आए। 2009 में उन्हें अमेठी और रायबरेली के करीब स्थित सुल्तानपुर से कांग्रेस टिकट पर जीत मिली। कार्यकाल समाप्त होने तक उन्हें अंदाजा हो चुका था कि उत्तर प्रदेश में हालात प्रतिकूल हैं। उन्होंने असम से राज्य सभा सदस्यता ले ली। वह कार्यकाल अब समाप्त हो रहा है, गांधी परिवार का प्रभाव भी पहले जैसा नहीं रहा, ऐसे में उन्होंने एक बार फिर भाजपा की शरण ली।

साक्षी महाराज का जन्म सचिदानंद हरि साक्षी के रूप में हुआ। वह पिछड़े लोथ समुदाय के चमकते सितारे थे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और साक्षी महाराज के संरक्षक कल्याण सिंह भी इसी समुदाय से थे। सन 1991 और 1996 में वह भाजपा के टिकट

पर लोकसभा पहुंचे। बावरी मस्जिद विध्वंस मामले में आरोपित के नाते वह वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध नजर आते। बहरहाल टिकट न मिलने पर उनको यह प्रतिबद्धता भी समाप्त हो गई और वह समाजवादी पार्टी में चले गए। मुलायम सिंह यादव ने प्रसन्नतापूर्वक पार्टी में उनका स्वागत किया। साक्षी महाराज ने कहा कि अब भाजपा की नीतियां गरीब विरोधी हो चुकी हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि जीत की संभावना के बावजूद उनका टिकट क्यों कटा था ? उन पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी सहयोगी ब्रह्म दत्त द्विवेदी की हत्या का आरोप था।

सन 2000 में मुलायम सिंह ने उन्हें राज्य सभा भेज दिया। इस बीच हत्या का मामला हल्का पड़ चुका था। जल्दी ही उन पर और दो भतीजों पर एक कॉलेज प्रधानाचार्य के सामूहिक बलात्कार का मामला चला। उन्हें एक महीना तिहाड़ जेल में बिताना पड़ा लेकिन द्विवेदी हत्याकांड की तरह इस मामले में भी वह सबूतों के अभाव में बरी हो गए। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हत्या और बलात्कार के मामलों में सबूत का न मिलना आम है। वैसे ही जैसे आपको हमेशा यह सुनिश्चित करना होता है कि आप जीतने वाले दल में रहें। सन 2002 तक उन्हें पता चल चुका था कि समाजवादी पार्टी में का कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने मुलायम पर जातिवाद, तानाशाही से लेकर पूंजीवादी होने तक के आरोप लगाए और पार्टी छोड़ दी। वह अनौपचारिक रूप से भाजपा के बागी कल्याण सिंह की राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के साथ आ गए जो लोथियों का दल था।

सन 2009 में सरकार ने उन पर फर्जी स्वयंसेवी संगठन बनाने और अवैध रूप से 25 लाख रुपये जुटाने का आरोप लगाया। उनकी अनुयायी और उनके एक कॉलेज की पूर्व प्रधानाचार्य सुजाता वर्मा पर उनका साथ देने का आरोप लगा। वह 2012 में दोबारा भाजपा में आ गए। सुजाता वर्मा की एक दिन आश्रम से लौटते वक्त हत्या हो गई। साक्षी और उनके सहयोगियों पर हत्या का आरोप लगा। वह भूमिगत हो गए और बाद में उन्होंने आत्मसमर्पण करके जमानत ले ली। 2013 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से प्राथमिकी की खारिज कराने की उनकी कोशिश नाकाम रही। अगले वर्ष उन्हें भाजपा ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। उनकी प्रतिष्ठा बहाल हुई और ऐसे विस्तारित करियर वाले नेता के बारे में हम शिकायत कर रहे हैं कि वह सीतापुर जेल में सेंगर का धन्यवाद करने क्यों गए ? तीनों नेताओं की कहानी बताती है कि राजनीतिक दलों के लिए जीत की संभावना ही एकमात्र मानक है। अपराधी होना, बलात्कार के आरोप और हत्या मायने नहीं रखते। हिंदी प्रदेशों में एक ही फॉर्मूला है स्थानीय वोट बैंक। यह जाति, माफिया शक्ति या दोनों के मिश्रण से बन सकता है। तब या तो आप विजेता होते हैं या दूसरों को जिताने की क्षमता रखते हैं।

आप आसानी से जीतने वाले पक्ष को चुन सकते हैं और हत्या, बलात्कार, लूट, दंगे, धोखाधड़ी और घोटालों के बावजूद बने रह सकते हैं। लेकिन तब तक जब तक कि वेंटिलेटर पर संघर्ष करती कोई किशोरी, उसका पिता और हत्याओं में कई लोगों को गंवा चुका परिवार सब कुछ नहीं गंवा देता।

जीन में उत्परिवर्तन को नाकाम करने वाली एएसओ तकनीक

सैन फ्रांसिस्को स्थित कंप्यूटर वैज्ञानिक रोहन सेठ की एक पोस्ट इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। सेठ और उनकी साथी जेन को करीब छह महीने पहले एक बच्ची हुई थी जिसका नाम उन्होंने लीडिया रखा। जन्म के कुछ समय बाद ही उस बच्ची को दौरे आने शुरू हो गए। इस दंपती को कई सघन परीक्षणों के बाद पता चला कि 'एक अहम जीन में हुआ छोट-सा उत्परिवर्तन बच्ची के मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर रहा है जिससे वह गहरी अक्षमता और पीड़ा की चपेट में है।'

जेन और रोहन ने अपने स्तर पर गहन छानबीन की और अपनी बच्ची जैसे लाखों बच्चों को बचाने वाले दल में रहे। सन 2002 तक उन्हें पता चल चुका था कि समाजवादी पार्टी में का कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने मुलायम पर जातिवाद, तानाशाही से लेकर पूंजीवादी होने तक के आरोप लगाए और पार्टी छोड़ दी। वह अनौपचारिक रूप से भाजपा के बागी कल्याण सिंह की राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के साथ आ गए जो लोथियों का दल था।

सन 2009 में सरकार ने उन पर फर्जी स्वयंसेवी संगठन बनाने और अवैध रूप से 25 लाख रुपये जुटाने का आरोप लगाया। उनकी अनुयायी और उनके एक कॉलेज की पूर्व प्रधानाचार्य सुजाता वर्मा पर उनका साथ देने का आरोप लगा। वह 2012 में दोबारा भाजपा में आ गए। सुजाता वर्मा की एक दिन आश्रम से लौटते वक्त हत्या हो गई। साक्षी और उनके सहयोगियों पर हत्या का आरोप लगा। वह भूमिगत हो गए और बाद में उन्होंने आत्मसमर्पण करके जमानत ले ली। 2013 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से प्राथमिकी की खारिज कराने की उनकी कोशिश नाकाम रही। अगले वर्ष उन्हें भाजपा ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। उनकी प्रतिष्ठा बहाल हुई और ऐसे विस्तारित करियर वाले नेता के बारे में हम शिकायत कर रहे हैं कि वह सीतापुर जेल में सेंगर का धन्यवाद करने क्यों गए ? तीनों नेताओं की कहानी बताती है कि राजनीतिक दलों के लिए जीत की संभावना ही एकमात्र मानक है। अपराधी होना, बलात्कार के आरोप और हत्या मायने नहीं रखते। हिंदी प्रदेशों में एक ही फॉर्मूला है स्थानीय वोट बैंक। यह जाति, माफिया शक्ति या दोनों के मिश्रण से बन सकता है। तब या तो आप विजेता होते हैं या दूसरों को जिताने की क्षमता रखते हैं।

आप आसानी से जीतने वाले पक्ष को चुन सकते हैं और हत्या, बलात्कार, लूट, दंगे, धोखाधड़ी और घोटालों के बावजूद बने रह सकते हैं। लेकिन तब तक जब तक कि वेंटिलेटर पर संघर्ष करती कोई किशोरी, उसका पिता और हत्याओं में कई लोगों को गंवा चुका परिवार सब कुछ नहीं गंवा देता।



तकनीकी तंत्र

देवांग्शु दत्ता

दवा बनाना संभव है। सेठ दंपती के एनजीओ 'लीडियन एक्सलरेटर' का मकसद एएसओ अनुसंधान का एक मुक्त डेटाबेस तैयार करना है। आनुवांशिक अभिव्यक्ति एक ऐसी प्रक्रिया के जरिये होती है जिसमें डीएनए में छोट-सा परिवर्तन (एमआरएनए) के माध्यम से राइबोसोम को सूचना भेजता है। राइबोसोम एक विशाल आणविक कारखाने जैसा होता है और यह सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। यह प्रोटीन बनाने के लिए एमआरएनए से मिली सूचना का इस्तेमाल करता है। एंटीसेंस पद्धति इस एमआरएनए को ही निशाना बनाती है ताकि एक उत्परिवर्तित जीन से आने वाली सूचना को रोका जा सके।

ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड के छोटे अवयव हैं। एंटीसेंस पद्धति में गलत बरतवा करने वाले जीन की पहले पहचान की जाती है और फिर एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को रासायनिक तौर पर संश्लेषित किया जाता है कि उस उत्परिवर्तित जीन के जरिये एमआरएनए को सूचना प्रेषित किए जाने पर रोक लगाई जा सके। यह अत्यंत विशिष्ट एवं सटीक निशाना होता है जिससे केवल एक व्यक्ति के लिए एक डिजाइनर दवा बनाई जा सके।

डीएनए के मामले में एमआरएनए की आनुवांशिक सूचना न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम में छिपी होती है। न्यूक्लियोटाइड्स तीन क्षार युग्मों के क्रम में समाविष्ट होते हैं। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स भौतिक रूप से एमआरएनए को जोड़ते हैं और एक खास प्रोटीन बनाने के लिए मिलने वाले एंटीसेंस को रोक सकते हैं। इस तरीके से थैलेसीमिया, रेटिनोडिस, मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, कैन्सर, एचआईवी और एड्स जैसी कई बीमारियों का

इलाज किया जा चुका है। प्रोटीन प्रसंस्करण में आरएनए को प्रभावित करने में एएसओ की भूमिका का पता दो दशक पहले चला था। एक कृत्रिम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड संरचना के एंटीसेंस प्रभाव का पहली बार प्रदर्शन जैमैनिक एवं स्टीफेंसन ने सत्र के दशक के आखिरी वर्षों में किया था।

लेकिन इन तकनीकों के इस्तेमाल में प्रगति की दर धीमी रही है। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने पहली एएसओ दवा विट्रावीन के वाणिज्यिक इस्तेमाल की इजाजत वर्ष 2016 में दी थी। पिछले साल जाकर बोस्टन चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल के डॉ. टिमोथी यू ने एक खास मरीज को आनुवांशिक समस्या के निदान के लिए पहली डिजाइनर एंटीसेंस दवा विकसित की थी। लेकिन रीढ़ की मांसपेशी में कमजोरी और डकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बनी एएसओ दवाओं को अभी मंजूरी मिलनी बाकी है।

यह तकनीक स्नायु एवं गैर-स्नायु संबंधी कई परिस्थितियों के इलाज में भविष्य में बदलाव लाने की क्षमता रखती है। लेकिन इसके महंगे एवं संभावित नकारात्मक प्रभावों की भी अध्ययन किया जाना चाहिए।

कंप्यूटर वैज्ञानिक कहते हैं कि वे गंभीर बीमारियों के इलाज संबंधी शोध में खुले मनों का हिस्सा बनने में यकीन करते हैं। उनका कहना है, 'शोध प्रक्रिया में खुलापन लाकर हम किसी भी संस्थान को एएसओ दवा के विकास में सक्षम बना सकते हैं। उसके आधार पर हम प्रभावोत्पादकता और सुरक्षक आंकड़ों का एक साइटा डेटाबेस बना सकते हैं। किसी खास मरीज के लिए डिजाइनर दवा विकसित करने वाले वैज्ञानिक भी अपने डेटा को इस कोष का हिस्सा बनाकर अपना अंशदान कर सकते हैं। अधिक सूचनाएं इकट्ठा कर हम एक गणना-पद्धति तैयार कर सकते हैं जिससे प्रयोगशाला के स्तर पर होने वाली काफी मेहनत में कमी लाई जा सकती है।' वैज्ञानिकों का मानना है कि हरेक इलाज के साथ हम अगले इलाज को लागत एवं समय दोनों में ही कटौती कर सकेंगे। नवीनतम तकनीक को एक सूत्र में पिरोने का यह असामान्य तरीका होगा।

कानाफूसी

कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष ?

शीला दीक्षित के निधन के बाद से ही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हो चुकी है। दरअसल पार्टी को अच्छी तरह मालूम है कि वह इस काम में अधिक देरी नहीं कर सकती है। कारण, दिल्ली में विधानसभा चुनाव करीब आ चुके हैं और राजधानी पर लंबे समय तक शासन कर चुकी कांग्रेस का इस समय वहां अस्तित्व ही नहीं नजर आ रहा है। इस बीच, शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व लोकसभा सांसद संदीप दीक्षित भी इस पद के बड़े दावेदारों में से एक हैं। इसके साथ ही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों जय प्रकाश अग्रवाल और सुभाष चोपड़ा भी इस पद के उतने ही प्रबल दावेदार हैं। इस बात की काफी संभावना है कि इस पद के लिए संदीप दीक्षित के नाम पर विचार किया जा सकता है। पहली बात तो यह कि संदीप दीक्षित की छवि बहुत साफ-सुथरी है और दूसरा हाल ही में शीला दीक्षित के निधन के बाद सहानुभूति का तर्क भी उनके पक्ष में काम कर सकता है। माना जा रहा है कि इन दोनों कारकों का लाभ उनको मिलेगा और संदीप दीक्षित दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकेंगे।



आपका पक्ष

कुपोषण खत्म करने की पहल

भोजन में पोषक आहार नहीं मिलने की वजह से कई लोग कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। इसका सीधा संबंध भोजन तथा खाद्यान्न से है। पहले जैविक खेती की जाती थी। खेतों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं होता था। गोबर या जैविक खाद के इस्तेमाल से खेती की जाती थी। इस वजह से फसल की उपज बढ़ती थी और फसल में पोषक तत्व मौजूद होते थे। आज अधिक फसल उत्पादन करने के लिए रासायनिक खेतों की जाती है। इससे फसल की उपज तो बढ़ जाती है लेकिन उसमें पोषक तत्वों की मात्रा घट जाती है। इसे समझने के लिए पोल्ट्री तथा देसी मुर्गी का उदाहरण लिया जा सकता है। पोल्ट्री मुर्गी के चूजे 15 से 20 दिन में बहुत बड़े हो जाते हैं। वहीं देसी मुर्गी के चूजों को बड़ा होने में छह माह तक का समय लग जाता है। इन दोनों में पोषक तत्वों का अंतर दिख जाता है। बहरहाल देश में कुपोषण खत्म



करने के लिए पोषक आहार पर जोर देने की जरूरत है। एक गरीब व्यक्ति दो वक्त का भोजन तो करता है लेकिन उसे भोजन के हिसाब से पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं जिससे वह कुपोषण का शिकार हो जाता है। उस व्यक्ति का शरीर उचित विकास नहीं कर पाता है तथा वह कमजोर दिखाई पड़ता है। सरकार की सितंबर माह

देश से कुपोषण समाप्त करने के लिए लोगों की भागीदारी जरूरी है

से राष्ट्रीय पोषण अभियान शुरू करने की योजना है। इस योजना में जहागीदारी की जरूरत है। आज भी कई गरीब बच्चों को तीन वक्त का भोजन नहीं मिल पाता है।

अगर उन्हें किसी तरह दो वक्त का भोजन मिलता भी है तो उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। अतः लोगों को भी इस अभियान में शामिल होकर कुपोषण को खत्म करने की दिशा में पहल करनी चाहिए। लोग अपने आसपास के बच्चों को किसी एक दिन पौष्टिक आहार का भोजन करा सकते हैं।

प्रियदर्शिनी शर्मा, नई दिल्ली

घाटी को शांत करने की कोशिश

जम्मू कश्मीर में 10 हजार सुरक्षा बलों की तैनाती से घाटी के नेताओं की नींद उड़ गई है। कश्मीर के कई बड़े नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्री ने इस मामले में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने सुरक्षा बलों की तैनाती से घाटी के लोगों में डर का माहौल

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।